

श्री हरिवंश: महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Shri Pratap Singh Bajwa, not here. Shri M.P. Veerendra Kumar, not here. Then, Dr. Vikas Mahatme.

Need to grant SC Status for Dhangar Community in Maharashtra

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ दिलाना चाहता हूँ। सर, महाराष्ट्र में धनगर का प्रश्न पिछले 70 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक उसे सुलझाया नहीं गया है। भारत के संविधान में धनगर को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे हिन्दी में लिखते समय धनगर के बजाय धनगड़ लिखा हुआ है। धनगड़ जनजाति का एक भी आदमी महाराष्ट्र में कहीं नहीं है, फिर इस जनजाति को महाराष्ट्र में आरक्षण कैसे मिल सकता है? यह आरक्षण धनगर जनजाति को ही दिया गया है, लेकिन आज भी धनगर जमात अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण से वंचित है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में धनगर को अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण देंगे। महोदय, मैं चाहता हूँ कि इस निर्णय को लागू करने के लिए जो भी संवैधानिक कार्यवाही हो, उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। महाराष्ट्र में धनगर समाज के जो लोग हैं, उनमें सरकार के खिलाफ बहुत असंतोष है, रोष है, जो कम होना चाहिए, अन्यथा यह असंतोष मराठा आरक्षण की तरफ बहुत बढ़ सकता है, जिससे आगे चलकर सरकार को बहुत परेशानी भी हो सकती है। यदि उनका आंदोलन हिंसक बन गया, तो सरकार बहुत मुसीबत में आ जाएगी। महोदय, सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार से जल्द से जल्द एक सिफारिश पत्र मंगवाकर तुरंत इस काम को किया जाए, ताकि जो भी धनगर लोग हैं, जो पिछले 70 सालों से इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं, वे इसका फायदा लेकर, संविधान में उनके लिए जो व्यवस्था है, उसका लाभ उठा सकें, और लोगों का रोष समाप्त हो सके, धन्यवाद।

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I associate myself with the matter raised by Dr. Vikas Mahatme.

SHRI VINAY DINU TENDULKAR (Goa): Sir, I also associate myself with the matter raised by Dr. Vikas Mahatme.

SHRI MAHESH PODDAR (Jharkhand): Sir, I also associate myself with the matter raised by Dr. Vikas Mahatme.

MR. CHAIRMAN: You know the system. The recommendation has to be made by the State Government. It is then sent to the Registrar General; then it is sent to the concerned Commission. Then, it goes to the Cabinet and then it comes to Parliament. Please talk to the State Government and impress upon them to send a recommendation. ...*(Interruptions)*... The Central Government asking the State to make a recommendation is not the way. ...*(Interruptions)*... Now, Shrimati Jharna Das Baidya.